Pradeep sorastriya_PAPER 2 Full 27-01-2022

14 March 2022 17:46

खंड-'अ'

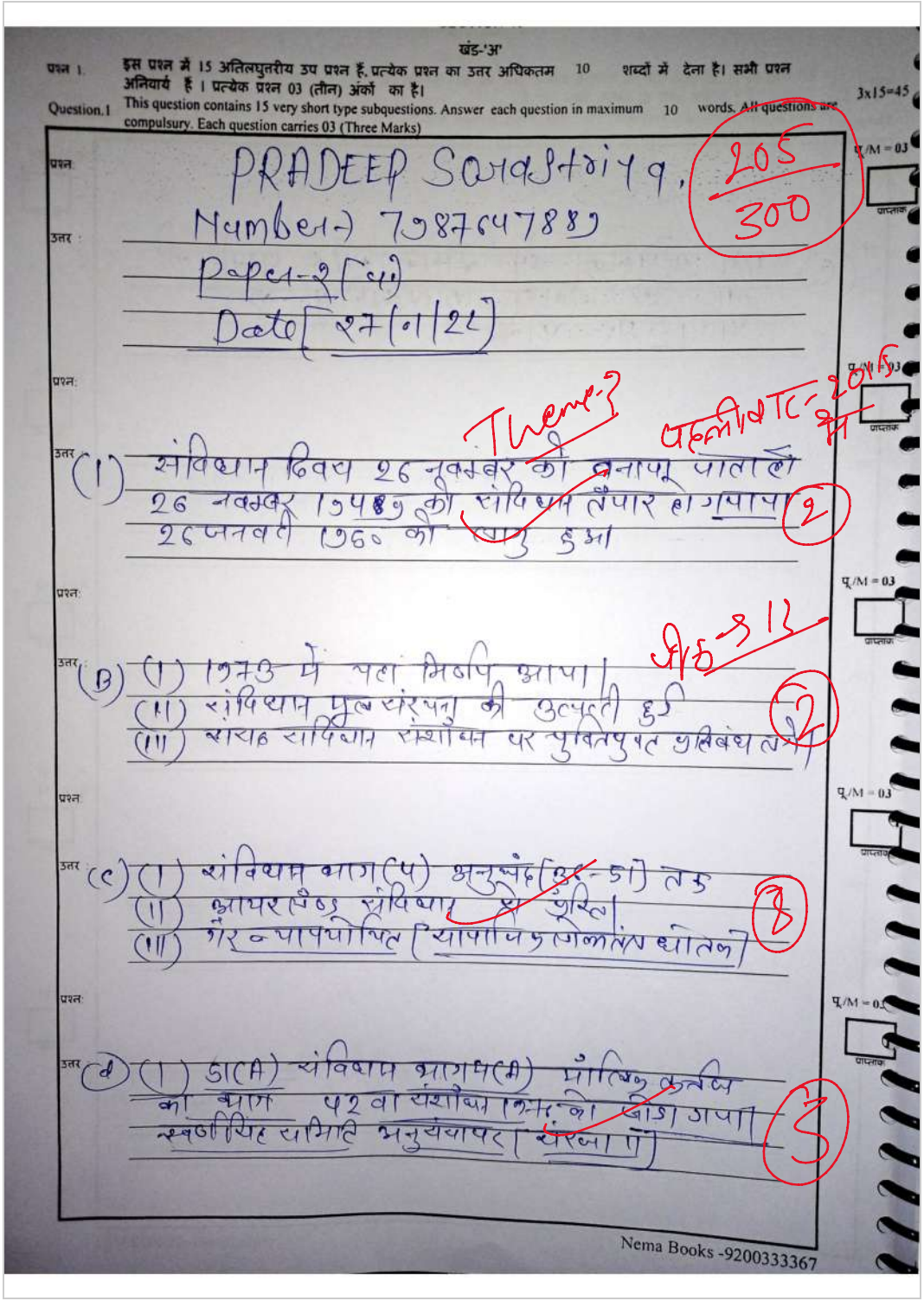

प्रश्न 1. इस प्रश्न में 15 अतिलघुत्तरीय उप प्रश्न हैं. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं । प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंकों का है।

Question.1 This question contains 15 very short type subquestions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsory. Each question carries 03 (Three Marks) 3x15=45

प्रश्न: PRADEEP Sorastriya, 205/300

उत्तर: Number- 7987647889
Paper-2 (ब)
Date [27/1/22]

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर: (1) संविधान दिवस 26 नवम्बर को मनाया जाता है 26 नवम्बर 1949 को संविधान तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ

Theme-? पहली बार TC-2015 में

2

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर: (B) (I) 1973 में यह निर्णय आया।
(II) संविधान मूल संरचना की उत्पत्ति हुई
(III) संसद संविधान संशोधन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगे।

नीति-313

2

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर: (c) (I) संविधान भाग (4) अनुच्छेद (36-51) तक
(II) आयरलैण्ड संविधान से प्रेरित।
(III) गैर-न्यायपोषित [सामाजिक लोकतंत्र द्योतक]

(हस्तलिखित अंक: अस्पष्ट)

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर: (d) (I) 51(A) संविधान भाग 4(A) मौलिक कर्तव्य को भाग 42वा संशोधन (1976) को जोड़ा गया स्वर्णसिंह समिति अनुशंसा पर [संख्या 11]

3

पू./M = 03 प्राप्तांक

(e) (1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा मिला (2018) अनुच्छेद 338(B) व उपखण्ड(क) जोड़ा गया। 1

(f) न्यायपालिका अपने निर्णय को लागू करने या पूर्ण न्याय प्रदान हेतु डिक्री आदेश जारी कर सकती है उदा.(BHU) गाड़ियाँ का निर्णय 1½

(g) कोई भी व्यक्ति या संगठन अन्य वर्ग समूह को न्याय दिलाने के लिए (PIL) तक न्यायालय तक जा सकता है। 1½

(h) सुशील चन्द्रा वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2021 में नियुक्त। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ती होती है 1½
324 अनुच्छेद-324

(i) मत दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1

compulsury. Each question carries 03 (Three Marks)

प्रश्न:

उत्तर: (J) (1) अनुबंध (O.S) द्वारा गठित | संरचना | अध्यक्ष शासन द्वारा निर्धारित अन्य सदस्य कार्य - राज्य भर्ती परिक्षा आयोजन करना

प्रश्न:

उत्तर: (K) समुदाय विशेष के हितो की पूर्ति हेतु बने संगठन जिनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना हो (CBO) कहलाता है

प्रश्न:

उत्तर: (L) जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते है वे समाजवादी नेता रहे, इनकी रचनाएं समाजवाद तथा, समाजवाद से सर्वोदय आदि है

प्रश्न

उत्तर: (m)

प्रश्न:

उत्तर: (N) सरकार की नीतियो का मूल्यांकन करने तथा उन्हे उत्तरदायी बनाने वाली विभिन्न संगठनात्मक इकाईया उदा - N.G.O, CBO, ट्रस्ट आदि

प्रश्न:

उत्तर : (O) सोशल मिडिया जैसे ट्विटर पर अपनी अभिव्यक्ति करना माइक्रोब्लॉगिंग कहा जाता है।

प्रश्न:

PART-B

प्रश्न: (2.2) पू./M =

उत्तर

(A) महालेखा परीक्षक (148) अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।
इसकी निम्न भूमिका है।

(i) सरकार वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना
(ii) सार्वजनिक वाणिज्य उपक्रमों की लेखा परीक्षा करना।
(iii) कुछ प्राप्तियों व व्यय, तथा अनुदान आदि की जाँच यही कार्य केंद्र राज्यों के लिए करता है।
(iv) लोकलेखा समिति को सहायता प्रदान करता है
(v) लोकहित में पारदर्शिता उत्पन्न करता है।
(vi) भ्रष्टाचार नियंत्रण, अनुशासनपूर्ण वित्तव्यवस्था आदि

3½

प्रश्न: (2.2) पू./M =

उत्तर

(B) NALSA अधिनियम 1987 के तहत (NALSA) एक वैधानिक निकाय है।

उद्देश्य → (i) सुगम-सुलभ न्याय तक पहुँच बढ़ाना
(ii) न्याय की लागत कम करना।

कार्य → (i) निःशुल्क विधिक सेवा अनुच्छेद 39(A) तहत प्रदान करता है।
(ii) वंचित वर्ग को कानूनी सहायता प्रदान करना
(iii) वंचित व गरीब वर्गों को वकील प्रदान करना
(iv) न्यायपालिका में मामला दर्ज करने में सहायता
(v) जिला अदालतों का आयोजन करना
(vi) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश देना।

5½

प्रश्न: (2.2)

उत्तर :

(c) विधि व कानून के पुर्णपालन हेतु नागरिक सहभागिता आवश्यक। निम्न प्रकार नागरिक निर्णय प्रक्रिया मे भागीदारी कर सकते है

(i) प्रत्यक्ष लोकतंत्र मे मतदान, रेफ्रेंडम, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकप्रतिनिधि चुन कर

(ii) समाचारपत्रो, मिडिया मे अपने विचार रखकर

(iii) संबंधित बिलो के सार्वजनिक करण तथा उस पर सुझाव देकर।

(iv) पंचायती स्तर पर ग्राम सभा के द्वारा।

(vi) एक विषय पर शहर मे लोगों से जनमत संग्रह

(v) संघठन, दृष्ट, सिविल सोसायटी के रूप मे शपथपूर्वक।

प्रश्न: (2.2)

उत्तर (d) निम्न प्रकारो से बदल सकता है।

(a) सकारात्मक कार्य की प्रशंसा कर उस धारणा को प्रोत्साहित करना उदा: बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ

(b) कुरीतियो के विरुद्ध जागरूक कर उसे समाप्त करने मे उदा: घर की बेटी, बेटी-बचाओ-बेटी पढ़ाओ

(c) भ्रष्टाचार का खुलासा कर तथा उसके कठोर दंड प्रदर्शित कर नकारात्मक मनोवृत्ती उत्पन्न करना।

(d) सरकारी के कार्य की वार्षिक समीक्षा कर मत समाज मे एंटीइंकंमबेंसी उत्पन्न कर सकता है

(e) समानता, बंधुत्व, सहिष्णुता भावना का प्रचार। उदा: हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई सब भाई भाई।

निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 (छः) अंकों का है। 5x10=5

Question 2 Write the answers of any ten of the following questions in maximum 50 words. Each question carries 6 (Six) marks.

प्रश्न: (2.2) पू./M = (

उत्तर :

(E) अन्त्योदय दीनदयाल द्वारा प्रतिपादित विचार है जिसके अनुसार संसाधनों का वितरण समाज के अंतिम वर्ग तक होना चाहिए। इस हेतु आवश्यक है- (i) सत्ता विकेन्द्रीकरण (ii) रोजगार अधिकार (iii) लघु-कुटीर उद्योग प्रोत्साहन (iv) संपत्ति सुरक्षा (v) कृषि विकास पर ध्यान दिया जाए।

4

प्रभाव → ग्रामीण रोजगार सृजन
प्रभाव → उपभोक्तावाद को बढ़ावा
प्रभाव → आर्थिक समानता को बल मिलेगा
प्रभाव ↓ सामाजिक न्याय प्राप्ति

प्रश्न: (2.2) पू./M = 0

उत्तर (F) मैक्स वेबर अनुसार शक्ति आरोपण की अभिव्यक्ति है जो लाभकारी रूप से होती है। वेबर ने इसके (5) प्रकार बताए

4

(i) वैधानिक शक्ति → पद की उत्तरदायित्व पूर्ति हेतु प्राप्त उदा. IAS, IPS।

(ii) संविदा शक्ति → योग्यता व कुशलता के कारण प्राप्त।

(iii) करिश्माई शक्ति → व्यक्तित्व व विश्वसनीयता के कारण उत्पन्न (उदा. गांधी, हिटलर)

(iv) पारितोषिक → कोई सुविधा, वेतन प्रदान करने के कारण प्राप्त उदा. कंपनी के मालिक की शक्ति

(v) उत्पीड़क → किसी वस्तु, सेवा, से वंचित करने के कारण उत्पन्न उदा. पुलिस, न्यायपालिका

निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 (छः) अंकों का है।

...stion 2 Write the answers of any ten of the following questions in maximum 50 words. Each question carries 6 (Six) marks.

...: (2.2)

उत्तर :

(ब) 74 वा संशोधन 1992 मे नगर निकायो के संवैधानिक स्थापना के लिए किया गया।

प्रावधान → (I) भाग 9(अ) अनुच्छेद (243 P - 243 ZG)

(II) अनुसूची 12 (विषय 18) जोड़े गए।

(III) त्रिस्तरीय नगरीय निकाय संरचना नगरनिगम, नगरपालिका, नगरपंचायत।

(IV) जिला (243ZD) महानगर (243ZE) नियोजन समिति स्थापना।

प्रभाव
→ शहरो के लिए स्थापना हेतु संवैधानिक बाध्यता
→ सत्ता का विकेन्द्रीकरण
→ शहरो का बेहतर प्रबंधन हुआ
→ जनभागीदारी को प्रोत्साहन

प्रश्न: (2.2)

उत्तर (4) राष्ट्रीय दल घोषित (ECI) द्वारा

(i) BJP (ii) BSP (iii) कांग्रेस (iv) NCP/राष्ट्रीय कांग्रेस (v) तृणमूल कांग्रेस (vi) CPI (vii) CPI(M)

आवश्यक शर्तें – (i) लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो।

(ii) लोकसभा चुनाव में 2% सीटें चार भिन्न-2 राज्यों से जीती हो।

(iii) तीन या तीन से अधिक राज्यों में राज्यस्तर दल घोषित किया गया हो।

प्रश्न: (2.2)

उत्तर (I) मिश्र प्रकार प्रयोगिता बनी हुई है।

(a) इसकी अब तक पहुंच डिजिटल डिवाइड से प्रभावित नहीं होता है।

(B) अधिक विश्वसनीय क्योंकि परम्परागत व लोगों के लिए अनुकूल

(c) बढ़ती फेक न्यूज, कार्पोरेट न्यूज चैनल हस्तक्षेप, 24x7 मीडिया चैनल आदि के कारण प्रिंट मीडिया लोगों के बीच अधिक विश्वसनीय व भरोसेमंद है।

(d) विस्तृत व सत्य सूचनाएं प्रदान करने में अधिक सहायक

(e) वस्तुपरक उपागम में स्वीकार्यता अधिक

SECTION -A
खंड-'अ'

प्रश्न: 2. निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 (छः) अंकों का है। 5x10=

Question.2 Write the answers of any ten of the following questions in maximum 50 words. Each question carries 6 (Six) marks.

प्रश्न: (2.2) पू./M =

उत्तर :

(J) लोकप्रशासन के कुमियाही सिद्धांत के प्रतिपादन में हैनरी फियोल, गिल्ट उर्विक, लूथर गुलिक प्रमुख योगदान हो।

प्रमुख सिद्धांत → (i) श्रम विभाजन → प्रत्येक श्रमिक, प्रबंधक, कार्य विभाजित हो (ii) पदसोपान की व्यवस्था (iii) सत्ता के प्रत्यायोजन की व्यवस्था (iv) स्थायी नियुक्ति (v) निश्चित वेतन (vi) क्रमबद्धता होनी चाहिए (vii) अधिकतम समन्वय (viii) संगठन के प्रति समर्पण (ix) समितियां व समन्वय (x) उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो (xi) केन्द्रीयकरण । आदि।

प्रश्न: (2.2) पू./M =

(A) संघवाद वह अवधारणा है जिसमें कुछ राज्य मिलकर एक केन्द्र का निर्माण करते है तथा उनके मध्य क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर संबंध होते है।

संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग है। कई संवैधानिक उपबंध व विशेषता इसकी पुष्टि करते है।

(I) भारत का लिखित संविधान।
(II) स्वतंत्र न्यायपालिका (124) Art
(III) द्विस्तरीय सरकार (केन्द्र-राज्य)
(IV) शक्तियों का विभाजन (सातवीं सूची)
(V) संविधान कठोर (368) तक
(V) द्विसदन प्रणाली (राजभागीदारी - राज्यसभा)

परन्तु के.सी. व्हियर ने इसे अर्द्धसंघीय कहा है इसके निम्न कारण।

(I) एकल संविधान की उपस्थिति।
(II) एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना
(III) एकल नागरिकता का प्रावधान।
(IV) राष्ट्रीय आपात काल व राष्ट्रपति शासन
(V) अखिल भारतीय लोक सेवा।

(5) राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति (केन्द्र) द्वारा।

(6) संघ सूची में अधिक महत्वपूर्ण विषय, अवशिष्ट शक्ति केन्द्र में निहित होना।

(7) संसद को ही संविधान संशोधन शक्ति प्राप्त। तथा समवर्ती सूची में प्राथमिकता।

(8) राज्यों को विभाजित करने, नाम परिवर्तन व सीमा विस्तार आदि अधिकार संसद को (Art 3)

(9) अनुच्छेद (249), (253) तहत संसद द्वारा राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण शक्ति आदि

उपरोक्त कारक संविधान की केन्द्रीय मुखौटे की प्रकृति को स्पष्ट करते है अर्थात् भारतीय संविधान प्रकृति पूर्ण संघीय न होकर अर्द्ध संघीय है।

परन्तु निम्न उपायो द्वारा संघात्मकता को बल दिया गया चाहे वो अंतराज्यीयपरिषद, जडा परिषद, क्षेत्रीय विकास परिषद या आदी परिषद आदि द्वारा या पंचायतीराज स्थापना कर के सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया अपितु भारतीय संघ अपनी प्रकृति में अनुरूप है जो समय अनुकूल है

7½

Nema Books -9200333367

प्रश्न: (3.1)

(B) न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य है। संसद या राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों व कानूनों की समीक्षा करना कि वे संविधान व मूल अधिकारों के विरुद्ध तो नहीं यदि हो तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है।

संविधान के निम्न अनुच्छेदों के तहत न्यायपालिका को पुनर्विलोकन शक्ति प्राप्त है
(I) मौलिक अधिकार (Art. 13-35)
(II) स्वतंत्र न्यायपालिका (124/214)
(III) शक्ति पृथक्करण अवधारणा।
(IV) नीति निर्देशक तत्व (Art. 37)
(V) संघात्मक व्यवस्था के तहत
(VI) कल्याणकारी राज्य अवधारणा तथा प्रस्तावना (सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय)
(VII) विभिन्न न्यायिक निर्णय (मिनर्वा मिल्स)

संसद द्वारा निम्न प्रकारों से न्यायिक पुनर्विलोकन पर प्रतिबंध लगाने के उपाय किए हैं

Nema Books -9200333367

(i) प्रथम संविधान संशोधन (नवी अनुसूची) न्यायिक समीक्षा बाहर रखेगी।

(ii) 24 वें संशोधन द्वारा असीमित संशोधन शक्ति संसद ने प्राप्त की।

(iii) 25 वें संशोधन द्वारा संशोधन समीक्षा शक्ति समाप्त की गयी।

(iv) 42 वे संशोधन द्वारा भी कम किया गया। [Art 31(B), 31(C)] द्वारा

न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में न्यायपालिका निर्णय :- (i) केशवानंद भारती वाद 1973 में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया।

(ii) मिनर्वा मिल्स 1980 वाद में इसे मूल संरचना भाग घोषित किया।

(iii) I.R. कोएल्हो वाद 2007 में नवी अनुसूची विषय इसके अंतर्गत लाए गए।

महत्व — राजनैतिक निरंकुशता पर नियंत्रण। संविधान की सुरक्षा।

(iv) मौलिक अधिकारों की सुरक्षा।

(v) कार्यपालिका-विधायिका की शक्ति सीमा निर्धारण में महत्व आदि।

न्यायिक समीक्षा बेहतर लोकतांत्रिक सरकार स्थापना का आधारभूत स्तंभ है।

प्रश्न: (3.1)

(c) भारतीय स्वतंत्रता को वर्तमान में (75) वर्ष हो रहे है परन्तु संविधान वादीयों ने जिस आधुनीक लोकतांत्रिक भारत का सपना देखा था वह अभी तक पूर्ण नही हो।

भारतीय लोकतंत्र अभी भी पूर्ण परिपक्व नही हो सका। भारतीय राजनिति के आप महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, व तकनीकी विकास ना होकर धर्म, जाति, को विषय महत्वपूर्ण बने हुए है। क्योंकि भारतीय राजनितिक दलों द्वारा राजनितिक विषय हेतु इनका प्रयोग किया जाता है

जिनके निम्न उदाहरण देखने को मिलते है

(1) धर्म → भारतीय राजनिति का यह महत्वपूर्ण मुददा जो धार्मिक ध्रुविकरण को उत्पन्न करता है जहा धर्म विशेष के प्रति सदभावना अन्य के प्रति नफरत उत्पन्न की जाती है। तथा

धर्म के आधार पर सीटो का आंवटन किया जाता है। U.P चुनाव 2022 में प. उ.प मे (50) मुस्लिम बहुल इलाको मे मुस्लिम प्रतिनिधि उतारे गया।

भारतीय

(ii) जाति → समाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओ में से एक है जाति भारतीय पहचान की मुख्य इकाई जिसके इसके नाम पर संगठन बनाए जाते है तथा वोटिंग की जाती है

उदा बिहार, उत्तरप्रदेश दलित, पिछडो की राजनीति

(iii) वर्ग → वर्ग विशेष का ध्रुविकरण भारतीय राजनीतिक विशेषता है जैसे कृषिकवर्ग का ध्रुविकरण, महिलावर्ग को लुभाना तथा आरक्षण की राजनीति। इस

असरियतवला का निवारण पर्याप्त शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कठोर चुनाव संहिता, जनजागरू का तथा राजस्टेट कड़िग जैसे उपायो से किया जा सकता है।

Nema Books -9200333367

(i)
सरकार के निर्णयों में जनभागीदारी व उनके नीतियों के उत्तरदायित्व निर्धारण में सिविल सोसायटी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
इन्ही सिविल सोसायटी के रूप में म.ज.स. व स्वयं सहायता समूह सरकारी नीती निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

(i) नागरिक मांगों को सरकार के सम्मुख पेश करना या मामलों को उठाना उदाहरण गुजरात से आरंभ (RTI) मांग आंदोलन जो (2005) RTI (Act) पारित करने में सफल रहा।

(ii) यह सरकार व लोगों के मध्य विचार विमर्श के सेतु के रूप में कार्य करते है।
उदाहरण म.ज.स. की मांग द्वारा ही 1984 परिवार न्यायालय स्थापित हुई।

(iii) यह विभिन्न नीतियो की समिक्षा उजागर कर कमीयो को उजागर करते है हाल ही मे (EIA) 2020 की कमीयो को उजागर किया गया।

(iv) वंचित वर्ग की मांगो तक को सरकार तक पंहुचाना तथा उनके हित मे नीतीया बनाना उदा मनरेगा। 8

(v) प्रशासन मे उत्तरदायित्व, पारदर्शिता की प्रेरणा सरकार को प्रदान करना।

(v) आवश्यक सुधारो के लिए सुझाव प्रदान करना उदा ASSER रिपोर्ट (प्रथम N.G.O)

सीमाऐ - (i) N.G.O का राजनीतिकरण

(ii) स्वयं सहायता समूहो मे जागरूकता

(iii) FCRA 2020 कानून।

(iv) मनी लांड्रिंग जैसे मामलो मे N.G.O से लाभ।

(v) ग्रामीण क्षेत्रो मे अशिक्षा (स्वयं सहायता समूह)

यह सिविल सोसायटी के वह भाग जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सरकारी नीतीयो के निर्माण मे सहयोगी होते है।

(E) राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत केन्द्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य स्तर राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया गया।

(ब) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग → अधिनियम
गठन - 12 अक्टूबर 1993

धारा-3 के तहत इसका गठन किया गया।
→ कुल → 6 सदस्य → 7 पदेन सदस्य

संरचना → (1) अध्यक्ष → पूर्व SC मुख्य न्यायधीश या अन्य न्यायधीश।

(2) न्यायिक सदस्य → (i) SC पूर्व न्यायधीश। 1 सदस्य
(ii) HC पूर्व न्यायाधीश। 1 सदस्य

(3) अन्य सदस्य → मानवाधिकार विशेषज्ञ
→ एक महिला सदस्य अनिवार्य

(4) 7 पदेन सदस्य → SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, दिव्यांगजन के लिए विशेष आयुक्त, बाल संरक्षण आयुक्त।

कार्य → (1) मानवाधिकार उल्लंघन पर जाँच करना
(11) स्वयं संज्ञान या शिकायत मिलने पर कार्यवाही करना।
(111) पिड़ित को क्षतिपूर्ति दिलवाने की सिफारिश करना
(1V) अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों को लागू करवाना।
(V1) न्यायालय में मानवाधिकार मामलों में पेश होना।
(V) राज्य पुलिस स्टेशनों, जेल, सुधारगृहों की जाँच।

(2) राज्य मानवाधिकार आयोग ÷ धारा 21 द्वारा बनाया गया।

(a) संरचना → कुल 3 सदस्य (अध्यक्ष सहित)
(1) → 1 अध्यक्ष → HC पूर्व मुख्य न्यायाधीश
(11) → 1 सदस्य → HC अधिवक्ता
(111) → 2 सदस्य → मानवाधिकार विशेषज्ञ
मध्यप्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापना इसी के तहत 1995 में की गयी।

कार्य → (1) राज्य स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन मामले की जाँच करना।

अतः यह दोनों आयोग भारत में मानवाधिकार सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ है।

कहलाता है।

PART-B

(A) (I) प्रस्तावना संविधान का भाग है परन्तु यह न तो विधायिका शक्ति का स्रोत है न ही उनकी शक्ति पर प्रतिबंध (केशवानन्द भारती वाद) 2

(B) (I) संघीय लोकसेवा आयोग से सम्बंधित संघ लोक सेवाओं के Article 1½
(II) राष्ट्रपति द्वारा आयोग स्थापना होगी
(IV) सदस्य नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।

(C) (I) धर्म जाति वर्ग (II) पंथनिरपेक्ष (III) धर्मनिरपेक्षता (नैतिक) (IV) सरकारी कार्य 0

(D) (I) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित
(II) उद्देश्य → उपभोक्ता विवाद का समाधान
धारा-17 द्वारा स्थापित [3] सदस्य 2½

प्रश्न:

उपाध्यक्ष- राजीव कुमार।

उत्तर (e) (i) स्थापना → 1 जनवरी 2015 → शासी परिषद
(ii) अध्यक्ष → प्रधानमंत्री, भाग- → विशेष सदस्य
→ पदेन सदस्य।
(iii) पद भारतीय थिंक टैंक है

1

प्रश्न:

उत्तर सटीक और दें

उत्तर (f) अनुच्छेद [25-28] तक विद्यमान है। धर्म को (25) अबाध रूप से मानने प्रचार-प्रसार करने, संस्था (26) स्थापना, करारोपण छूट (27) धार्मिक शिक्षा (28)

2

धर्मप्रसार की स्वतंत्रता

प्रश्न:

उत्तर (g) वल्लभभाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रियासतों को एकीकरण किया था।

2

प्रश्न:

उत्तर (h) अनुच्छेद 243(a) द्वारा स्थापित → ग्राम सभा जो ग्राम की प्रत्येक सदस्य यह पंचायत विधायी इकाई है।

2½

प्रश्न:

उत्तर (i) (i) आतंकवाद (ii) नक्सलवाद (iii) अलगाववाद (iv) क्षेत्रवाद (v) साइबर हमले व आक्रमण (vi) बाह्य युद्ध (vii) बम विस्फोट आदि।

2

(J) (I) 1 अध्यक्ष -> राज्यपाल द्वारा नियुक्त।
(II) अन्य सदस्य -> राज्यपाल द्वारा निर्धारित उन्हीं के द्वारा नियुक्त।

वर्तमान - अध्यक्ष + 4 सदस्य

1

(K) (I.) राजनैतिक दबाव, (II) निष्पक्ष ढांचा अभाव (III) कार्पोरेट हस्तक्षेप व कड़िंग (IV) केन्द्रीय की बदली संरचना (V) 2427 मॉडल।

2

(L) दी वेडिंग ऑफ वीजा, दी पुनर्विभाजन ऑफ कारट, चाहत ऑफ पाकिस्तान।

3

(M) (I) 243(M) के तहत राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण संबंध पारित करना।
(II) 312(A) नवी अखिल भारतीय सेवा का सृजन

1.5

(N) महात्मा गांधी विचार विमर्श संबंधी लोगों के अधिकतम कल्याण पर ध्यान दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने अपनाया।

2

1) (I) लैंगिक (II) आर्थिक (III) व्यापारिक
(IV) नस्लीय (V) ~~जातिय~~ | राजनैतिक |

2

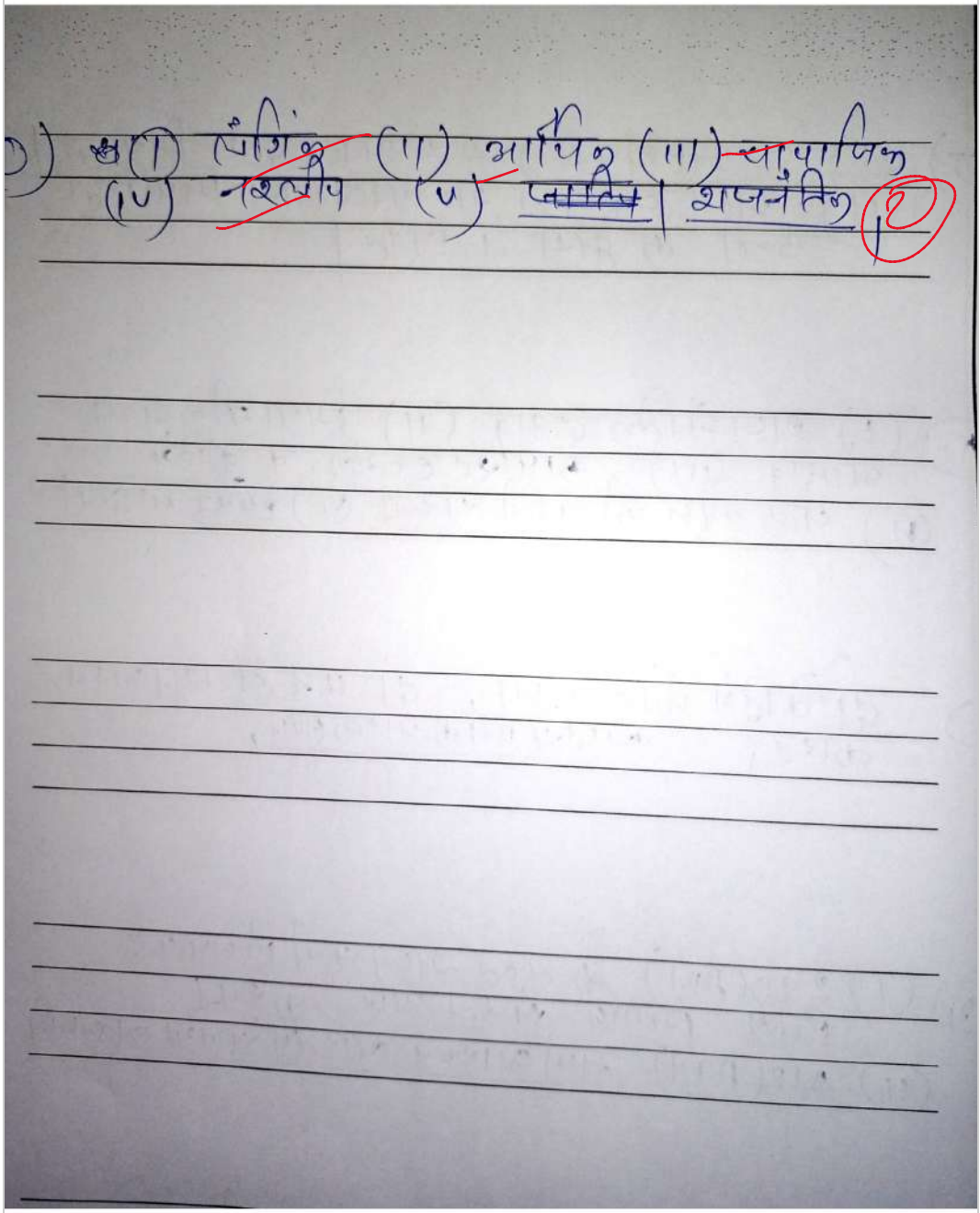

(A) बहुदलीय व्यवस्था से तात्पर्य एक लोकतांत्रिक राज्य में एक से अधिक राजनैतिक दलों की भागीदारी से है।

भारत ने अपने संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया।

यह व्यवस्था कई मामलों में सफल सिद्ध हुई।

(I) राजनैतिक निरकुंशता पर नियन्त्रण
(II) विस्तृत वर्ग, जाति, धर्म, के लोगों के हितों की पूर्ति को बढ़ावा।
(III) एक निश्चित विचारधारा का अधिकार होने पर रोक लगायी।
(IV) भिन्न-भिन्न विचारधाराओं ने आवश्यकता होने पर सफल गठबंधन किया।

परन्तु यह बहुदलीय प्रणाली (1951 - 2014) कई चुनौतियों को उत्पन्न करने का कारण बनी।

(i) (1952-67) तक एकदलीय शासन हावी रहा।
(ii) केन्द्र-राज्य भिन्न दल उपस्थिति ने विवाद को जन्म दिया।
(iii) राजनैतिक लाभ हेतु क्षेत्रीय मुद्दों का विरोध
(iv) धर्म/जाति आधारित दलों का उदय।
(v) कई दलों ने भाषा, क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन दिया।
(vi) (1988-92) तक अस्थिर सरकार का बड़ा कारण बहुदलीय व्यवस्था रही।
(vii) दलबदल द्वारा सरकारों को हटाया जाना
(viii) चुनावों की आवृत्ति ने उनके खर्च को बढ़ाया
(ix) अनेक दलों की उपस्थिति (फर्स्ट-पास्ट द पोस्ट) प्रणाली में अल्पमत सरकार स्थापना करती है।

परन्तु भारत में अनेक दलों के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर (6) दल ही सक्रिय हैं। तथा बहुदल प्रणाली नागरिकों को अधिक विकल्प व प्रतिनिधि अवसर देती है। पिछले 12 वर्षों में भारतीय व्यवस्था अनेक कमियाँ रही है जिन्हें चुनाव सुधारों के द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।

Nema Books -920033336

(B) संविधान संशोधन संसद द्वारा अनुच्छेद (368) के तहत किया जाता है।

प्रक्रिया – (i) किसी भी सदन में प्रस्ताव लाना।

(ii) दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित हो (संघीय विषयों होने पर आधे से अधिक राज्य सामान्य सहमति)

(iii) अंत में राष्ट्रपति अनुमति देने हेतु बाध्य होगा।

(a) प्रथम संशोधन → 1951 में कर संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के बाहर होंगे। (I.R. कोहेलो वाद के बाद न्यायिक समीक्षा में शामिल) – 2007।

(b) 42वां संशोधन → 1976 में किया गया मिनि संविधान कहा गया।

Nema Books -9200333367

(I) अनुच्छेद 51(A) शामिल कर मौलिक कर्तव्य जोड़े।

(II) अनुच्छेद 39(b), 48(a), 51(a) निदेशक तत्व जोड़े

(III) निदेशक तत्व को अधिक प्राथमिकता मौलिक अधि।

(IV) समवर्ती सूची में वन, वन्यजीव, शिक्षा, मापतौल विषय शामिल किए गए।

(3) 52 वां संशोधन → 1985 में किया गया जिसके तहत (10) अनुसूची को जोड़ कर दलबदल निरोध अवैध बनाया गया।

(4) 73 वां संशोधन → (I) पंचायती राज स्थापना 1993 भाग 9 (अनुच्छेद 243-243O) शामिल किया

(II) ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़कर 29 विषय पंचायत को सौंपे गए

(IV) त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत

(5) (101) संशोधन → (2016) में किया गया।

(I) जडा कर व्यवस्था लागू (केन्द्र व राज्य) कर का एकीकरण

(II) अनुच्छेद 279A → जडा परिषद की स्थापना।

(c) नवीन लोक प्रबंधन से तात्पर्य है निजि क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों को सार्वजनिक प्रबंधन में शामिल करना। सर्वप्रथम यह शब्द क्रिस्टोफर हुड द्वारा प्रतिपादित किया गया।

इसके निम्न नवीन आयाम

(1) विनौकरशाहीकरण → लालफीताशाही, सरकारी नियंत्रण कम करना। उदारवादी प्रबंधन पर बल।

(II) तकनीक → पेशेवर प्रबंधन पर बल निजि क्षेत्र तकनीक को शामिल करना उदा० (ई-गवर्नेंस)।

(III) राजकोषीय नियम → सार्वजनिक व्यय अपव्यय नियंत्रण तथा व्यय में अनुशासन उदा० FRBM Act 2003।

(IV) विकेन्द्रीकरण → केन्द्रीकरण का विरोध तथा सत्ता विकेन्द्रीकरण व जनभागीदारी उदा० पंचायती राज।

(V) निजि भागीदारी → PPP के आधार पर सरकार निजि सहयोग।

Nema Books -9200333367

(6) प्रबंधन में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ावा (RTI, द्वितीय ARC)।

विकास प्रशासन → वह प्रशासन जो विकास लक्ष्यों पर केन्द्रित।
U.L. गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित।
इसके निम्न आयाम :-

(a) परिवर्तनवादी → यथास्थिति का विरोध स्थिति अनुकूलता पर बल।
(B) लक्ष्यन्मुखी → निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्ति प्रयास।
(C) नियोजनवादी → संसाधन के बेहतर प्रयोग हेतु योजना बनाना।
(d) परिणामन्मुखी → प्राप्त परिणामों को मूल्यांकन करना।
(e) जनभागीदारी → लोगों को नीति निर्माण में शामिल करना।

कहना उचित होगा विकास प्रशासन व नवीन लोकप्रबन्ध एक-दूसरे के विकास को प्रोत्साहित करते हैं तथा वर्तमान वैश्वीकरण, उदारीकरण इनकी महती आवश्यकता।

(I) संविधान भाग (4) में अनुच्छेद (36-51) तक नीति निदेशक सिद्धांत जोड़े गए हैं।

इसके निम्न उद्देश्य हैं

→ सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना।

→ राज्यों को नीति निर्माण में सहायता।

→ सरकारों को उत्तरदायी बनाना।

→ सामाजिक-आर्थिक समानता व न्याय की स्थापना।

निदेशक तत्वों में निम्न गांधीवादी तत्व शामिल

(I) अनुच्छेद 40 (पंचायतों की स्थापना)

(II) अनुच्छेद 43 (कुटीर व लघु उद्योग को बढ़ावा)

(III) अनुच्छेद 46 → अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़े (आर्थिक-शैक्षणिक) के लिए विशेष प्रावधान करना।

(IV) अनुच्छेद 47 → मद्य निषेध को लागू करना।

(V) अनुच्छेद 48 → दुधारू पशुओं के वध पर रोक तथा पशु नस्ल में सुधार किया जाए। तथा कृषि में नयी तकनीक अपनायी जाए।

गांधीवादी सिद्धांतो ने निम्न प्रकार शासन को प्रभावित किया।

(I) सत्ता का विकेन्द्रीकरण के लिए प्रोत्साहित किया (73/74) संशोधन पंचायती राज व्यवस्था।

(II) ग्रामीण विकास व लघु कुटीर उद्योग हेतु नीति निर्माण पर बल। राष्ट्रीय खादी बोर्ड, मनरेगा, DPMRCM।

(III) मद्य निषेध, इसकी बिक्री पर प्रतिबंध के लिए बाध्य बनाया। 85% पैकेट पर केवल चेतावनी।

(IV) पशुवध पर रोक (गोवध निषेध अधिनियम), व निरन्तर किए जा रहे पशु नस्लो मे सुधार

(V) वंचित SC/ST वर्ग हेतु SC/ST अधिनियम पुरस्कृत आयोग व आरक्षण व्यवस्था।

(VI) कृषि क्षेत्रो मे नई तकनीकी को अपनाकर राज्य क्षेत्र बना।

अतः गांधीवादी निर्देशक सिद्धांतो ने शासन को जनकेन्द्रित ग्राम केन्द्रित व रोजगार केन्द्रित बनाने मे पहली भूमिका निभाई।

8½

(E) संविधान अनुच्छेद 32 के तहत SC व (226) के तहत HC को रिट क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी की जाती है

(I) बंदी प्रत्यक्षीकरण → किसी को अनैतिक, मिथ्यापराध रूप में बंदी बनाने के विरुद्ध उसे संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है।

(II) परमादेश → न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद कार्यरत व्यक्ति से अपने कार्य व उत्तरदायित्व पूर्ति न करने पर जारी की जाती है कार्य हेतु आदेश दिया जाता है।

(III) प्रतिबंध → (रोकना) अधिनस्त न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य करने पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है।

(IV) उत्प्रेषण → अधिनस्त द्वारा हस्तक्षेप करने पर संबंधित मामले को स्वयं के पास मंगवाना।

Nema Books -92003333

प्रश्न: (3.1) Continued (जारी)

(5) अधिकारपृच्छा → किसी सार्वजनिक पद पर कार्यरत व्यक्ति से उस पद के पर उसके दावे के विरुद्ध जारी होती है।

(SC व HC) दोनो के क्षेत्राधिकार मे कुछ भिन्नताए पायी जाती है।

(a) SC केवल मौलिक अधिकार उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता (HC) अन्य विषयो पर भी।

(B) SC संघी संविधि कानूनी विषयो के मामलो पर तथा सम्पूर्ण देश की क्षेत्राधिकार पर लागु होती है। वही (HC) रिट क्षेत्राधिकार की सीमा वह राज्य है अन्य राज्य व्यक्ति पर तब लागु होगा जब मामले से जुड़ा हो।

(C) SC रिट अधिकार मूल है वह वादी को मना कार्यवाही हेतु मना नही कर सकता HC का यह अधिकार वैकल्पिक निर्णय पर आधारित।

अतः स्पष्ट है कि HC का रिट क्षेत्राधिकार SC से अधिक विस्तृत है।

न: (2.2)

उत्तर : (A) प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम -2002 द्वारा प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया (2003)

संरचना → (1) अध्यक्ष व अन्य (6) सदस्य होते हैं

→ केन्द्र द्वारा नियुक्ति।

→ अध्यक्ष → पूर्व HC/SC न्यायधीश हो या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुभवी या विधिवेत्ता।

भूमिका → (1) प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों की जाँच

(2) बाजार एकाधिकार पर नियंत्रण।

(3) प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों पर रोक लगाकर पीड़ित की क्षतिपूर्ति करना।

(4) व्यापार प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता अधिकार को बढ़ावा देना

उत्तर :

(B) संविधान भाग (XII) अनुच्छेद (268-293) तक वित्तीय संबंध स्थापित।

(I) कर विभाजन → संघ (12) विषय राज्य (15) विषय समवर्ती सूची पर केन्द्र करारोपण अधिकार।

(II) करदायित्व → (I) अनुच्छेद 268 → केन्द्र द्वारा आरोपित राज्य द्वारा अधिग्रहित व उपभोग।

(III) अनुच्छेद 269 → केन्द्र द्वारा आरोपण-अधिग्रहण किन्तु राज्यों-केन्द्र के मध्य विभाजित।

(IV) अनुच्छेद 272 → केन्द्र द्वारा ही आरोपण-अधिग्रहण अन्य (सरचार्ज-सेस)।

(V) विधिक अनुदान, वित्त आयोग, आदि संबंध निर्धारित

प्रश्न: (2.2)

उत्तर :

(C) निम्न उद्देश्यों के कारण नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता को स्थापित किया।

(I) शीत युद्ध में अपनी स्वायत्ता बनाए रखना (II) वैश्विक गुटबाजी से देश को सुरक्षा (III) शीत युद्ध में तृतीय ध्रुव का निर्माण (IV) उपनिवेशिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दी (V) विश्व में शांति व समृद्धि हेतु वैश्विक शांति संतुलन (VI) दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

(VII) राष्ट्र संप्रभुता बनाए रखना। (क)

(VIII) साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध

...questions in maximum 50 words. Each question carries 6 (Six) marks.

प्रश्न: (2.2)

पू./M =

उत्तर (D) लोक प्रशासन का भिन्न महत्व है।

(I) राजनैतिक नीति निर्माण व उसके सफल क्रियान्वन मे

(II) राष्ट्र मे शांति व सुव्यवस्था बनाए रखना।

(III) वाणिज्य सेवाओ का सृजन करना।

(IV) सामाजिक न्याय प्राप्ति व आर्थिक विकास

(V) आर्थिक असमानता को नियंत्रित कर समावेशी विकास पर बल।

(V) रोजगार का सृजन करने वाला माध्यम

(VI) सामाजिक जागरूकता व परिवर्तन का कारक।

8

प्रश्न: (2.2)

पू./M =

उत्तर (E) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत आयोग 1992 में स्थापित। 31 जनवरी

संरचना → 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य

अध्यक्ष नाम → रेखा शर्मा

भूमिका → (I) संवैधानिक - वैधानिक महिला अधिकारों की सुरक्षा।

(II) महिला अधिकार उल्लंघन मामलों की जांच।

(III) केन्द्र को नीति निर्माण मे सहायता।

(IV) महिला संबंधि मामलो को न्यायपालिका पहुंचाना।

(V) पिड़िता हितैषी, अन्य सहायता, संरक्षण कार्य।

4

उत्तर :

(F) विकास प्रशासन से तात्पर्य है जो नियोजित तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक लक्ष्य प्राप्ति करे।

विशेषता → (I) यह लक्ष्य अनुमुखी प्रशासन।
(II) यह पारदर्शिता व उत्तरदायित्व पर केन्द्रीत
(III) यह परिवर्तनशील व परिणामनमुखी।
(IV) यह पदसोपान को अस्वीकार करता है
(V) यह सत्ता के विकेन्द्रीकरण व अधिकतम जनभागीदारी को प्रोत्साहन।
(V) यह तकनीकी को शामिल करता है
(V) धारका करता है नीति, रणनीति, योजना, परियोजना.

प्रश्न: (2.2)

उत्तर : (G) हैनरि फियोल अनुसार सत्ता आदेश देने व कार्य करवाने की शक्ति है।
इसके निम्न प्रकार है
(I) सूत्र सत्ता → जिसके आदेश बाध्यकारी हो। उदा. न्यायपालिका
(II) स्टाफ सत्ता → आदेश सलाहकारी उदा. सचिव
(III) क्रियात्मक → सूत्र सत्ता का विशेष उद्देश्यपूर्ति हेतु स्टाफ सत्ता में स्थानांतरण।
मैक्स वेबर ने भी तीन प्रकार बताये
(I) परम्परागत → धर्म, रीति-रिवाज → शपथ धारणा
(II) करिश्माई व्यक्तित्व → गांधी, हिटलर, मंडेला
(III) कानूनी सत्ता → संविधान या कानून से प्राप्त।

उत्तर :

(H) विभिन्न उद्देश्य पूर्ति हेतु निर्मित कोई भी गैर-लाभकारी संगठन सिविल सोसायटी माना जाता है।

सार्वजनिक आंदोलन में भागीदारी –
(i) नागरिक मांगों को उठाती है
(ii) सार्वजनिक नीतियों का मूल्यांकन।
(iii) सरकार को उत्तरदायित्व बनाती है
(iv) भ्रष्टाचार पर नियंत्रण व पारदर्शिता प्रोत्साहित
(v) सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रोत्साहन।
उदा. बचपन बचाओ, हेल्पएज इंडिया भ्रष्टाचार विरोधी (CS) है

3½

प्रश्न: (2.2)

उत्तर: (I) 2005 अधिनियम की धारा 5 द्वारा स्थापित इनकी निम्न भूमिका।
(i) प्रशासन में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ाना।
(ii) प्राधिकरणों को सूचना प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध करना।
(iii) लोगों की सूचना तक पहुंच बढ़ाना तथा सूचना न मिलने पर शिकायत निवारण, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना।
(iv) सूचना अधिकारियों का कर्तव्यहीनता पर दण्ड देकर उत्तरदायी बनाना।

3½

SECTION -A

खंड-'अ'

प्रश्न: 2.
Question.2

निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 (छः) अंकों का है।

Write the answers of any ten of the following questions in maximum 50 words. Each question carries 6 (Six) marks.

प्रश्न: (2.2)

उत्तर :

(ग) (i) विज्ञानवादी उपागम → टेलर द्वारा प्रतिपादित

विशेषता → (i) कार्य को विज्ञान के रूप में विकसित करना (ii) उचित अनुसंधान व प्रमाणित सिद्धांतों को संगठन में अपनाना।

(iii) योग्यता आधार पर लोगों का चयन करना

(iv) प्रबंधक व श्रमिकों के मध्य अधिकतम समन्वय

(v) आर्थिक प्रोत्साहन पर बल → विभेदीकृत मजदूरी।

(ii) मानव संबंध उपागम → एल्टन मेयो।

(i) मानवीय संबंध पर बल (ii) अधिकतम मानवीय संतुष्टि पर बल (iii) श्रमिक व प्रबंधक में सहयोग।

(iv) अनौपचारिक संगठन को महत्व आदि।

3